AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International

ISSN:2320-3714
Volume: 3 Issue:3
September 2022
Impact Factor: 6.3
Subject: Humanities

भारत में बाल श्रम का एक सामाजिक–आर्थिक विश्लेषण

सुदेश चौधरी [1], प्रोफ. (डॉ.) आर. के. एस अरोडा[2]
[1]शोधार्थिनी, शिक्षा विभाग, भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान, भारत
[2]शोध निर्देशक, शिक्षा विभाग, भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान, भारत

DECLARATION: I AS ANAUTHOR OF THIS PAPER/ ARTICLEHERE BY DECLARE THAT THE PAPER SUBMITTED BY ME FOR PUBLICATION IN THIS JOURNALIS COMPLETELY MY OWN PREPARED PAPER. I HAVE CHECKED MY PAPER THROUGH MY GUIDE/SUPERVISOR/EXPERT AND IF ANY ISSUE REGARDING COPYRIGHT / PATENT/ PLAGIARISM/ OTHER REAL AUTHOR ARISE THE PUBLISHER WIL NOT BE LEGALLY RESPONSIBLE IF ANY OF SUCH MATTER OCCUR PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENT FROM THE JOURNAL.

सारांश – दुनिया के बच्चे मासूम, कमजोर और आश्रित होते हैं। वे सभी जिज्ञासु, सक्रिय और आशा से भरे हुए हैं। उनका जीवन आनंद और शांति, खेल, सीखने और बढ़ने से भरा होना चाहिए। उनके भविष्य को सद्भाव और सहयोग से आकार देना चाहिए। उनका बचपन परिपक्व होना चाहिए, क्योंकि वे अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाते हैं और नया अनुभव प्राप्त करते हैं। बच्चों को छोड़ना, उनके लिए जीवन की अच्छी नींव को छोड़कर, मानवता के खिलाफ अपराध है। बच्चे कल तक इंतजार नहीं कर सकतेय वे हर रोज बढ़ते हैंय उनके साथ–साथ आसपास के बारे में जागरूकता की भावना बढ़ती है। कल कोई जवाब नहीं हैय उनकी वर्तमान देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास समय की मांग है। हम पहले से ही संविधान, निर्देशक सिद्धांतों और बाल अधिकार पर कन्वेंशन द्वारा उन्हें दिए गए अधिकारों से निपट चुके हैं। बाल श्रम को केवल कानून द्वारा पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है, जब तक कि समाज के वंचित वर्ग के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के पूरक न हों। यह 11–13 वर्ष आयु वर्ग के बीच सबसे अधिक प्रचलित (80%) देखा गया। यह माता–पिता की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में कमी के साथ बढ़ता है। आधे से भी कम (46.7%) बाल श्रमिकों को दिन में 6 घंटे से अधिक काम करना पड़ता था। काम की औसत अवधि प्रति सप्ताह 6.1 दिन है। आर्थिक भूमिका निभाने के लिए बच्चों के आग्रह को कम करने के लिए बालिकाओं की रक्षा करने, परिवार के आकार में कमी की वकालत करने और माता–पिता की शिक्षाध्आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द – बाल मजदूर, काम करने की स्थिति, काम करने का माहौल

परिचय

बच्चे मानवता के लिए सबसे बड़ा उपहार हैं और बचपन मानव विकास का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली चरण है क्योंकि यह किसी भी समाज के भविष्य के विकास की क्षमता रखता है। बच्चे जो एक ऐसे वातावरण में पले–बढ़े हैं, जो उनके बौद्धिक, शारीरिक और सामाजिक

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International

ISSN:2320-3714
Volume: 3 Issue:3
September 2022
Impact Factor: 6.3
Subject: Humanities

स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, बड़े होकर समाज के जिम्मेदार और उत्पादक सदस्य बनते हैं। प्रत्येक राष्ट्र अपने भविष्य को अपने बच्चों की वर्तमान स्थिति से जोड़ता है। जब वे कार्य के लिए बहुत छोटे होते हैं तो काम करके, बच्चे अपने वर्तमान कल्याण या अपनी भविष्य की आय अर्जन क्षमताओं को या तो अपने भविष्य के बाहरी विकल्प सेट को कम करके या अपनी भविष्य की व्यक्तिगत उत्पादक क्षमताओं को कम करके अनुचित रूप से कम कर देते हैं। अत्यधिक आर्थिक संकट के तहत, बच्चों को शैक्षिक अवसरों को त्यागने और नौकरी करने के लिए मजबूर किया जाता है जो ज्यादातर शोषक होते हैं क्योंकि उन्हें आमतौर पर कम भुगतान किया जाता है और खतरनाक परिस्थितियों में लगे होते हैं। माता–पिता अपने बच्चे को खराब आर्थिक स्थिति के कारण एक हताश उपाय के रूप में नौकरी में संलग्न करने के लिए भेजने का निर्णय लेते हैं। इसलिए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गरीब परिवार मुख्य रूप से अपने बच्चों को कम उम्र में ही काम पर भेज देते हैं। बाल श्रम का एक विचलित करने वाला पहलू यह है कि बच्चों को शिक्षा की कीमत पर काम पर भेजा जाता है। स्कूल में उपस्थिति दर पर बाल श्रम का एक मजबूत प्रभाव पड़ता है और बच्चे के कार्य दिवस की लंबाई उसके स्कूल जाने की क्षमता से नकारात्मक रूप से जुड़ी होती है। बाल श्रम बच्चों के शिक्षा के उपयोग और लाभ के अधिकार को प्रतिबंधित करता है और स्कूल जाने के मौलिक अवसर से वंचित करता है। इस प्रकार, बाल श्रम बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बाल श्रम को ''कार्य स्थितियों के रूप में परिभाषित करता है, जहां बच्चों को अपने और अपने परिवार के लिए जीविकोपार्जन के लिए नियमित रूप से काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, और परिणामस्वरूप वे एक ऐसी स्थिति में शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े रहते हैं जो शोषक है। और उनके स्वास्थ्य और उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर दिया जाता है, अक्सर शैक्षिक और प्रशिक्षण के अवसरों से वंचित किया जाता है और उन्हें समय से पहले वयस्क जीवन (प्स्व) जीने के लिए मजबूर किया जाता है। 1948 का कारखाना अधिनियम कहता है कि कोई भी बच्चों द्वारा किए गए कार्य जो उनके पूर्ण शारीरिक विकास, वांछनीय न्यूनतम शिक्षा के उनके अवसर या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा मनोरंजन की आवश्यकता को या तो मजबूरी विकास के तहत बाधित करते हैं या एक संगठित या असंगठित न्यूनतम शिक्षा में स्वेच्छा से बच्चे के लिए उनके वांछनीय अवसर, बाल श्रम' (कारखाना अधिनियम 1948) कहा जाता है। बाल श्रम के सबसे बुरे रूप वे स्थितियाँ हैं जहां बच्चे एक दिन में नौ घंटे से अधिक काम करते हैंय न्यूनतम मजदूरी से कम कमाएं या बिल्कुल भी मजदूरी न करेंय स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरनाक परिस्थितियों में काम करनाय शिक्षा तक पहुंच नहीं हैय और, अपने परिवार के घर से बाहर काम करते हैं। बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं, वे अपनी उम्र और शारीरिक शक्ति के कारण कमजोर होते हैं और वे अपने भविष्य की योजना नहीं बना सकते हैं और किसी भी कार्य के परिणाम को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए उन्हें शोषण से बचाना

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International

ISSN:2320-3714
Volume: 3 Issue:3
September 2022
Impact Factor: 6.3
Subject: Humanities

चाहिए और उनके शारीरिक और मानसिक विकास के अवसर दिए जाने चाहिए। इसलिए बच्चों की सुरक्षा राष्ट्र की जिम्मेदारी है। भारतीय संविधान बच्चों को उनके शोषण से बचाने और हमारे समाज से बाल श्रम को खत्म करने के लिए भी सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय संविधान बच्चों के लिए प्रावधान करता है, जैसे कि अनुच्छेद –24 में यह प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाने या दिमाग में काम करने के लिए या किसी खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। भारत सरकार भी इस लक्ष्य पर काबू पाने के लिए हमारे देश में बच्चों की सुरक्षा, अधिकार और विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार ने विभिन्न कानून बनाए हैं जैसे कि बच्चों को विशेष रूप से खतरनाक और खतरनाक गतिविधियों में काम करने से रोकना बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986।

भारत में संवैधानिक सुरक्षा गार्ड

भारत का संविधान बच्चों के प्रति राज्य के रवैये की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति करता है, संविधान का अनुच्छेद –15 (3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने के लिए अधिकृत करता है। अनुच्छेद –21 किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद –21 ए – राज्य 6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को इस तरह से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है। अनुच्छेद –23 – मानव का अवैध व्यापार और भिखारी तथा अन्य प्रकार के बलात् श्रम निषिद्ध हैं और इस स्थिति का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। अनुच्छेद–24 में यह प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 39 (ई) घोषणा करता है कि राज्य यह सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी नीति बनाएगा कि आर्थिक आवश्यकता से मजबूर स्वास्थ्य को उनकी उम्र या ताकत के अनुकूल व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया जाए। अनुच्छेद 39

(ई) यह आदेश देता है कि बचपन और युवावस्था को शोषण से, नैतिक और भौतिक परित्याग के खिलाफ संरक्षित किया जाना है। संविधान के अनुच्छेद–45 में सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद, 38, 42, 43, 45 और 47 के तहत सामान्य प्रावधान, हालांकि सीधे बाल कल्याण से संबंधित नहीं हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए रणनीति प्रदान करते हैं। अनुच्छेद–38(1) में प्रावधान है कि राज्य प्रभावी रूप से सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, क्योंकि यह एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित कर सकता है जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुनिश्चित किया जाएगा। अनुच्छेद–42 और 43 काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International

ISSN:2320-3714
Volume: 3 Issue:3
September 2022
Impact Factor: 6.3
Subject: Humanities

को सुनिश्चित करने के लिए प्रदान करते हैं और एक वादा करते हैं कि राज्य उपयुक्त कानून, आर्थिक संगठन या किसी अन्य तरीके से सभी श्रमिकों के लिए निर्दिष्ट शर्तों के साथ एक जीवित मजदूरी सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। एक सभ्य जीवन स्तर और अवकाश और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के पूर्ण रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए काम करना। इसमें निश्चित रूप से व्यापक अर्थों में बाल श्रमिक शामिल हैं। अनुच्छेद–46 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का विशेष ध्यान रखते हुए पदोन्नति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद–47 राज्य द्वारा लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने पर जोर देता है। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। इन प्रावधानों की प्रगति और क्रियान्वयन का आकलन करते समय उल्लेखनीय है कि बाल श्रम दिन–ब–दिन बढ़ता ही जा रहा है।

बाल श्रम के संरक्षण के लिए विधायी प्रावधान

कारखाना अधिनियम (1881) बच्चे को परिभाषित करने और 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार के लिए निषेधात्मक नियमों को निर्धारित करने वाला पहला कानून था। कारखाना अधिनियम, (1911) ने बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में काम पर रखने और रात के समय काम करने पर रोक लगा दी। आईएलओ के पहले सम्मेलन ने बच्चे की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 15 वर्ष करने के लिए अधिनियम में अनिवार्य संशोधन (1922) किया। हालांकि, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को जहां रोजगार के लिए प्रतिबंधित किया गया है। अधिनियम के तहत 1935 में आयु बढ़कर 13 वर्ष हो गई। कारखाना अधिनियम, (1948), किसी भी कारखाने में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन के लिए निषेधात्मक नियम निर्धारित करता है। भारत खान अधिनियम, (1952) किसी भी भूमिगत खदान में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है। वृक्षारोपण श्रम अधिनियम, (1951) 12 वर्ष से कम आयु के रोजगार पर रोक लगाता है। मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट (1961) मोटर ट्रांसपोर्ट में बच्चों के रोजगार पर पूरी तरह से रोक लगाता है। विभिन्न राज्यों के दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, दुकानों, होटलों, ढाबों, गली की दुकानों और व्यावसायिक स्थानों में बच्चों के रोजगार पर भी रोक लगाते हैं। जो युवा नौकरीपेशा हैं, ये कानून अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं। रात के काम को प्रतिबंधित करते हुए, वे युवा व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। साथ ही, जो माता–पिता अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करते हैं, वे अपने बच्चों की उम्र के बारे में झूठ बोलते हैं। उपरोक्त कानूनों के अलावा, प्रशिक्षु अधिनियम, (1961), बीड़ी और सिगार श्रमिक (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, (1966), परमाणु ऊर्जा अधिनियम, (1962) और अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, (1970) ये अधिनियम प्रदान करते हैं कि बच्चों को रोजगार देना एक दंडनीय अपराध है। जैसा कि प्स्ट कन्वेंशन द्वारा आवश्यक है और जैसा कि 1975 में बच्चों के रोजगार पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में परिकल्पित

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International

ISSN:2320-3714
Volume: 3 Issue:3
September 2022
Impact Factor: 6.3
Subject: Humanities

था, बच्चों के शोषण को रोकने के लिए, भारत सरकार ने बाल श्रम के निषेध से निपटने के लिए एक एकल अधिनियम को लागू करने के लिए महसूस किया।
बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 में अधिनियमित किया गया था। अधिनियम ने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कुछ व्यवसायों और प्रक्रियाओं में रोजगार पर रोक लगा दी थी। इनमें यात्रियों का परिवहन, माल और मेल और रेलवे और बंदरगाहों में अन्य खतरनाक काम, बीड़ी बनाने, सीमेंट निर्माण, माचिस और विस्फोटकों का निर्माण, अभ्रक काटने, साबुन निर्माण, ऊन की सफाई और भवन और निर्माण उद्योग जैसी प्रक्रिया शामिल हैं। अधिनियम का तीसरा भाग न्यूनतम काम के घंटे निर्धारित करके, रात में काम पर रोक लगाकर, ओवरटाइम काम पर रोक लगाकर, और साप्ताहिक अवकाश द्वारा काम की शर्तों के नियमों का प्रावधान करता है। साथ ही, अधिनियम बाल श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए उपाय प्रदान करता है। इसने किसी भी संगठन द्वारा नियोजित बच्चों के विवरण वाले एक रजिस्टर के रखरखाव पर जोर दिया। कुछ व्यवसायों और प्रक्रियाओं में रोजगार पर रोक लगाते हुए, कानून ने अन्य मामलों में बच्चों के रोजगार को वैध बनाया।
ऐसी कुप्रथाओं के लिए अप्रत्यक्ष समर्थन दिया गया, जिन्हें रोजगार की प्रकृति के बावजूद पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में कई विशेषताएं हैं जो बाल केंद्रित हैं।

बाल श्रम के मूल कारण

बाल श्रम एक सामाजिक–आर्थिक समस्या है। गरीबी के कारण माता–पिता को अपने बच्चों को बाल श्रम से प्राप्त आय के पूरक के लिए भेजना पड़ता है, हालांकि परिवार को बनाए रखने के लिए अल्प आवश्यक हैं।
एक बच्चे के लिए बाल श्रम के रूप में काम करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करने वाले प्रमुख कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं।

- सामाजिक–आर्थिक पिछड़ापन
- गरीबी
- निरक्षरता
- बेरोजगारी
- अधिक जनसंख्या
- शिक्षा सुविधाओं का अभाव
- शिक्षा के महत्व के बारे में माता–पिता की अनभिज्ञता।
- श्रम के बच्चों पर प्रभाव की अनभिज्ञता।
- सरकार की उदासीनता

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International

ISSN:2320-3714
Volume: 3 Issue:3
September 2022
Impact Factor: 6.3
Subject: Humanities

विभिन्न सामाजिक वैज्ञानिकों का मानना है कि बाल श्रम रीति–रिवाजों, पारंपरिक रवैये और स्कूल की कमी या माता–पिता की अपने बच्चों को स्कूल, शहरीकरण, औद्योगीकरण, प्रवासन आदि में भेजने की अनिच्छा जैसे कारकों का एक उत्पाद है। बाल श्रम के लिए जिम्मेदार उपरोक्त कारकों के अलावा, कई अन्य कारण भी हैं। सबसे पहले, सुरक्षात्मक श्रम कानूनों के प्रावधान एकतरफा हैं और कृषि और लघु उद्योगों को कवर नहीं करते हैं। दूसरे, राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रवर्तन मशीनरी लगभग हर जगह अपर्याप्त हैं और बाल श्रम पर रोक लगाने में विफल हैं। बच्चे ज्यादातर मूक श्रोता या उनके लिए बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों के गैर–सुनने वाले होते हैं और इसलिए, उनकी समस्याओं को ठीक से महसूस नहीं किया जाता है, जिसके लिए कोई भी उनकी दुर्दशा पर गंभीरता से ध्यान नहीं देता है और बाल श्रम की रोकथाम के लिए दिए गए सुरक्षा उपायों को लागू नहीं किया जाता है। प्रभावी रूप से। आर्थिक वैश्वीकरण बाल श्रम के विकास के लिए समान रूप से जिम्मेदार है।

भारत में बाल श्रम की भयावहता पिछले दो दशकों में परिमाण और कार्यबल भागीदारी दर दोनों के मामले में भारी गिरावट देखी गई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों से प्राप्त साक्ष्य बताते हैं कि 2009–10 के दौरान भारत के बाल कार्यबल का अनुमान 2003 में 21.5 मिलियन (21.55 मिलियन) की तुलना में नौ मिलियन (9.07 मिलियन) से थोड़ा अधिक था। इस अवधि के दौरान, बच्चों की संख्या बाल रोजगार में 12.48 मिलियन की तेजी से गिरावट आई है। लड़कियों की तुलना में लड़कों में बाल श्रमिकों में काफी गिरावट देखी गई है। 2003 से 2009–10 के दौरान लड़कों और लड़कियों के कर्मचारियों की संख्या में गिरावट क्रमशः 12. 06 से घटकर 4.76 मिलियन और 9.49 से 4.31 मिलियन हो गई है। वास्तव में, 1990 के दशक की शुरुआत में लड़कों और लड़कियों (लड़कों के खिलाफ प्रतिकूल) के बीच मौजूद लिंग अंतर हाल के वर्षों में लगभग समाप्त हो गया है, यह अंतर 2.57 मिलियन से घटकर लगभग 0.45 मिलियन हो गया है। हालांकि, पूर्ण संख्या में, समस्या बड़ी है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 5–14 वर्ष के आयु वर्ग में 1.26 करोड़ आर्थिक रूप से सक्रिय बच्चे हैं। 2001 की जनगणना में यह 1.13 करोड़ थी।

एनएसएसओ सर्वेक्षण 2009–10 के अनुसार, कामकाजी बच्चों की अनुमानित संख्या 49.84 लाख है जो गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाता है। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित बाल श्रम पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में 5– से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की गतिविधि दर 5.1 प्रतिशत है, जो दुनिया में सबसे कम है। एशिया–प्रशांत क्षेत्र में, यह 18.8 प्रतिशत है। उसकी तुलना में, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बच्चों की गतिविधि दर 5 प्रतिशत है।

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International

ISSN:2320-3714
Volume: 3 Issue:3
September 2022
Impact Factor: 6.3
Subject: Humanities

वर्तमान परिदृश्य

2001 की भारतीय जनगणना के अनुसार, भारत में चौदह वर्ष से कम आयु के 11.28 मिलियन कामकाजी बच्चे हैं। सरकार के अनुसार, यह 2011–12 में 1.25 करोड़ (2011 की जनगणना) से घटकर 90.75 लाख और हाल ही में योजना, 2012 की वार्षिक रिपोर्ट से पता चला है कि 49.6 लाख (छैव का 66वां दौर) हो गया है। बाल श्रम अभी भी एक बड़ी समस्या है। भारत में। बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित हिंदी पट्टी में देश में 1.27 करोड़ कामकाजी बच्चे हैं, जो खतरनाक और गैर–खतरनाक दोनों तरह के व्यवसायों और प्रक्रियाओं में लगे हुए हैं। 5–14 आयु वर्ग के 19 लाख से अधिक बाल मजदूर उत्तर प्रदेश में हैं। राजस्थान में 12.6 लाख से अधिक श्रमिक हैं, इसके बाद बिहार और झारखंड में 11 लाख से अधिक और मध्य प्रदेश में 10.6 लाख श्रमिक हैं। हालांकि, 2011 की जनगणना के अनुसार, 5–14 आयु वर्ग के कामकाजी बच्चों के राज्यवार वितरण में, आंध्र प्रदेश 13.6 लाख बाल श्रम के साथ राष्ट्रीय सूची में यूपी के बाद दूसरे स्थान पर है।

भारत सरकार द्वारा लागू श्रम कानून, विधान में एक वर्ष तक की कैद और अधिकतम रु. बाल श्रम को रोजगार देने के लिए 20,000। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 1986 में बाल श्रम कानून की स्थापना के बाद से केवल 1360117 निरीक्षणों की पहचान की गई है, जिनमें से मुश्किल से 49092 पर मुकदमा चलाया गया है और केवल 4774 नियोक्ताओं को दोषी ठहराया गया है। (योजनाः नवंबर 2012)

तालिका I: भारत में कामकाजी बच्चों पर यूनिसेफ की रिपोर्ट

बच्चों का विवरण	आयु वर्ग के बच्चे (5–14 वर्ष)					
	बच्चों की संख्या (100 में)			बच्चों की संख्या (% में)		
	लड़के	लड़कियाँ	कुल	लड़के	लड़कियाँ	कुल
घरेलू कर्तव्यों में संलग्न	3865	37305	41170	00.30	03.15	01.67
केवल घरों के लिए सामानों के संग्रह, सिलाई, बुनाई में संलग्न)	3189	23714	26903	00.25	01.92	01.26
स्कूलों में भाग लेना	926180	745816	1671996	72.98	61.45	67.44
काम पर बच्चे	60017	116318	176335	04.73	08,93	06.75
आर्थिक गतिविधियों में लगे बच्चे	53806	45712	99518	04.18	03.86	04.02
बच्चे न तो काम पर और न ही स्कूल में	228398	251167	479565	17.26	20.42	18.80

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International

ISSN:2320-3714
Volume: 3 Issue:3
September 2022
Impact Factor: 6.3
Subject: Humanities

चुनौतियां

नीचे दिए गए पैराग्राफ में, शोधकर्ता ने बाल श्रम के कारण आने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियों को प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार हैं:

बच्चों के विरुद्ध हिंसा :

अधिकांश परिवारों में, माता–पिता अपने बच्चों की उपेक्षा करते हैं, देखभाल करने वाले उन्हें पीटते हैं और कार्यस्थलों में नियोक्ता उनका यौन शोषण करते हैं, इससे बच्चों के भावनात्मक, शारीरिक और यौन शोषण की समस्या बढ़ रही है, यह हमारे देश में समाजशास्त्रियों और मनोचिकित्सकों का ध्यान आकर्षित करने में विफल रहा है। . जनता और सरकार भी इसे एक गंभीर समस्या के रूप में पहचानती है। कुछ अध्ययन ''बाल दुर्व्यवहार'' शब्द को ''उन बच्चों तक सीमित करते हैं जिन्हें दुर्घटना के बजाय जानबूझकर गंभीर शारीरिक चोट लगी है''। लेकिन बाल शोषण की किसी भी परिभाषा को तब तक मान्य नहीं माना जा सकता जब तक कि इसमें मानसिक चोट और उपेक्षा और बच्चे के साथ दुर्व्यवहार जैसे गैर–शारीरिक कार्य शामिल न हों। बाल शोषण को आमतौर पर तीन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: शारीरिक, यौन और भावनात्मक।

स्ट्रीट चिल्ड्रेन:

स्ट्रीट चिल्ड्रेन शहरी सामाजिक अस्वस्थता का प्रतीक हैं। वे शहरी भारतीय बच्चों की सबसे कमजोर श्रेणियों में से हैं, और इन्हें स्ट्रीट क्रॉसिंग, फुटपाथ, फ्लाईओवर के नीचे, रेलवे प्लेटफॉर्म, बस स्टेशन, पार्किंग स्थल, बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर देखा जा सकता है। उन्हें स्ट्रीट चिल्ड्रन कहा जाता है क्योंकि वे दिन का एक बड़ा हिस्सा रोजगार, आश्रय, साहचर्य, या इधर–उधर घूमने के लिए सड़क पर बिताते हैं। ये बच्चे कभी स्कूल नहीं गए हैं या कुछ समय बाद स्कूल छोड़ चुके हैं। लगभग 90 प्रतिशत अपने परिवारों के साथ संबंध रखते हैं और 10 प्रतिशत अपने दम पर हैं, ये मुख्य रूप से वे हैं जिन्हें छोड़ दिया गया है या दुर्व्यवहार के दुरुपयोग से बच गए हैं, परिवार के टूटने की उपेक्षा करते हैं, या गरीबी का विरोध करते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) में, सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए सहायता अनुदान का एक अलग केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम शुरू किया गया था। कुछ राज्य सरकारें इन बच्चों की सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता भी प्रदान करती हैं। कुछ अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों ने परियोजना अनुदान के साथ सहायता प्रदान की है। 1998 में भारत सरकार ने देश में 'चाइल्ड लाइन इंडिया' की स्थापना की। चाइल्ड लाइन सेवाएं उन बच्चों की आपातकालीन जरूरतों के लिए प्रतिक्रिया करती हैं जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है, और वे अलग–अलग परिस्थितियों में होते हैं। क्योंकि उन्हें मूलभूत आवश्यकता प्राप्त करने का अधिकार है।

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International

ISSN:2320-3714
Volume: 3 Issue:3
September 2022
Impact Factor: 6.3
Subject: Humanities

बाल तस्करी :

मानव तस्करी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अपराध है। भारत में मानव तस्करी की मात्रा में वृद्धि हुई हैय 2010 में दर्ज मामलों की संख्या 3991 थी जो 2011 में घटकर 3029 और 2012 में 2848 हो गई। तस्करी के शिकार लगभग 60: 0ि 18 वर्ष से कम उम्र के हैं। ज्यादातर लड़कियों की तस्करी यौन उद्देश्य के लिए की जाती है। दुनिया भर में यौन शोषण या सस्ते श्रम के लिए सालाना आधार पर तस्करी किए गए बच्चों की संख्या 1.2 मिलियन है। लगभग 1,50,000 महिलाओं और बच्चों की हर साल दक्षिण एशिया से तस्करी की जाती है और उनमें से अधिकांश के लिए भारत मूल और गंतव्य के देश के रूप में कार्य करता है। कुछ अन्य मामलों में भारत के माध्यम से महिलाओं और लड़कियों की तस्करी दूसरे देशों में की जाती है। ऐसा अनुमान है कि लगभग 5000 से 7000 नेपाली लड़कियों को यौन शोषण के लिए भारत लाया जाता है।

भारतीय स्तर पर बाल श्रम पर काबू पाने के प्रयास

बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 1974: 22 अगस्त 1974 को अपनाई गई बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पिछले कुछ दशकों में शुरू की गई कई राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों के आधार के रूप में है, और इसके लिए नीतिगत ढांचा है। योजना। यह नीति निर्धारित करती है कि राज्य बच्चों को जन्म से पहले और बाद में और उनके पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए विकास के चरणों के दौरान पर्याप्त सेवाएं प्रदान करेगा, नीति में बच्चों के संतुलित विकास के उपायों की आवश्यकता पर बल दिया गया हैय बच्चों की उपेक्षा, क्रूरता और शोषण से रक्षा की जाएगी। बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति अगस्त 1987 में अपनाई गई थी जिसमें बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए कार्य योजना शामिल है। इसमें विधायी कार्य योजना और जहां भी संभव हो बच्चों को लाभान्वित करने के लिए सामान्य विकास कार्यक्रम के अभिसरण की परिकल्पना की गई थी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) देश में बाल श्रम के रोजगार के बारे में गहराई से चिंतित है क्योंकि यह संविधान और अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों द्वारा गारंटीकृत बच्चों के बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित करता है। आयोग अपने विशेष रिपोर्टरों, सदस्यों के दौरे, संवेदीकरण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं, परियोजनाओं की शुरूआत, उद्योग संघों और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ बातचीत, राज्य सरकारों और गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय के माध्यम से देश में बाल श्रम की स्थिति की निगरानी करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए लिया गया। आयोग का मानना है कि जब तक 14 साल की उम्र तक सभी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की वास्तविकता का एहसास नहीं हो जाता, तब तक बाल

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International

ISSN:2320-3714
Volume: 3 Issue:3
September 2022
Impact Factor: 6.3
Subject: Humanities

श्रम की समस्या बनी रहेगी। आयोग में बाल मजदूर हैं। भारत के कालीन उत्पादक जिलों में ऐसे कई स्कूलध्प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत हैं। बाल श्रम के मुद्दों के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता के स्तर में भी एक विशिष्ट सुधार हुआ है।

प्रत्येक बच्चे के अधिकार के रूप में प्रारंभिक शिक्षा : शिक्षा के लिए निवेश राष्ट्र के लिए निवेश है। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण निवेश है जो कोई भी विकासशील देश अपने भविष्य के लिए कर सकता है। बाल श्रम को कम करने के लिए शिक्षा सबसे प्रभावी उपकरण है। लेकिन भारत में प्रारंभिक शिक्षा को गंभीरता से लिया गया है और यह विचार का विषय है। यह शहरी वंचित बच्चों, बालिकाओं और विकलांग बच्चों की शिक्षा की उपेक्षा और कम बजटीय आवंटन की विशेषता है। निरंतर और दृढ़ता वकालत अभियान की खोज के रूप में, संसद ने भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए 93वां संविधान संशोधन विधेयक 2001 पारित किया।

सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए भी भोजन का अधिकार सुनिश्चित करना: बच्चों का कुपोषण देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। यह बच्चों की सीखने की क्षमता और दैनिक जीवन की समस्या से निपटने की क्षमता सहित उनकी वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। पुरुष बच्चों की तुलना में महिला बच्चे अधिक कुपोषित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुपोषण अधिक है। एक्शन एड का अनुमान है कि भारत में 212 मिलियन लोग पुरानी भूख और अल्पपोषण से पीड़ित हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार 2010 के वैश्विक भूख सूचकांक में 84 विकासशील देशों में भारत 67वें स्थान पर है। भोजन मनुष्य की श्रेणीबद्ध आवश्यकता में प्रथम है। इसलिए, उपलब्ध संसाधनों पर खाद्य सुरक्षा का पहला प्रभार होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा ''एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए बच्चों सहित सभी लोगों की पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक उनकी आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य वरीयताओं को पूरा करने के लिए पहुंच'' है। भोजन सहित अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन व्यतीत करना ''कृषि मंत्रालय के अनुसार, 2008 में भारत में दूसरी सबसे बड़ी कृषि योग्य भूमि (184 मिलियन हेक्टेयर) और 55 मिलियन हेक्टेयर की सबसे बड़ी सिंचित भूमि है। देश गेहूं (72 मिलियन टन), दालों का सबसे बड़ा उत्पादक (15 मिलियन टन), दूध (90 मिलियन टन), मसाले और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी):
राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, जो केवल 12 जिलों की संख्या के साथ शुरू हुई थी, देश के 21 राज्यों में 271 जिलों के कवरेज के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में उत्तरोत्तर विस्तारित की गई है, जो बाल श्रम के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International

ISSN:2320-3714
Volume: 3 Issue:3
September 2022
Impact Factor: 6.3
Subject: Humanities

बच्चों के लिए डे केयरः

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए देखभाल केंद्रों की आवश्यकता है। स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक विकास के संबंध में, बचपन देखभाल की अवधि है। अधिकांश कामकाजी महिलाएं कैजुअल वर्कर या स्वरोजगार के रूप में कम वेतन वाली नौकरियों में हैं। शहरी क्षेत्रों में कम आय वाले सेवा क्षेत्र और प्रसंस्करण उद्योगों में बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। परिवारों के परमाणुकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के साथ उनकी समस्याएं बढ़ गई हैं, माता–पिता को अपने बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी छोड़ दी गई है, भले ही वे अस्तित्व के लिए अपनी दैनिक लड़ाई लड़ रहे हों। संगठित क्षेत्र की महिला श्रमिक विधायी रूप से नियोक्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं सृजित करने की हकदार हैं। हालांकि, कवर की गई महिला श्रमिकों की संख्या बहुत कम है। नियोक्ता यह दिखाने के लिए सरल तरीके खोजते हैं कि क्रेच आयोजित करने के लिए श्रमिकों की संख्या न्यूनतम आवश्यक से कम है। वे अपने दायित्व को कम करने के लिए काम को आउटसोर्स भी करते हैं। कुछ प्रशिक्षित श्रमिकों के प्रभार में कार्य कर रहे हैं। बच्चों को पूरक पोषण और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अन्य मामलों में, हालांकि, क्रेच केवल प्रति कार्यकर्ता तरीके से चलाए जाते हैं। कुछ स्वायत्त निकायों और सरकारी विभागों ने अपने कर्मचारियों के लिए क्रेच स्थापित किए हैं। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कम आय वाले परिवारों के 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्रेच सेवाएं आयोजित करने के लिए गैर–सरकारी संगठन को सहायता प्रदान कर रहे हैं।

निष्कर्ष

बाल श्रम को दूर करने और बाल श्रम के परिणामस्वरूप आने वाली स्थितियों से बचने के लिए बाल कल्याण के लिए भारत के संविधान में बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संगठन भी इसी उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है जो बाल शोषण से मुक्त हो। पेपर के विभिन्न खंडों में चर्चा किए गए हालिया आंकड़े बताते हैं कि हम बाल श्रम को खत्म करने में कितने दूर हैं और हमें गरीब, अज्ञानी और अनसुने बच्चों के कल्याण के लिए कितनी मेहनत करने की जरूरत है। इस पत्र में हमने कुछ प्रमुख कदम प्रस्तावित किए हैं जो बाल शोषण को कम करने के योग्य साबित हो सकते हैं, इसलिए एक सुरक्षित और शुद्ध समाज।

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International

ISSN:2320-3714
Volume: 3 Issue:3
September 2022
Impact Factor: 6.3
Subject: Humanities

संदर्भ

- आनंदराजकुमार पी (2004)। महिला बाल श्रम। नई दिल्लीः ए पी एच पब्लिशिंग कार्पोरेशन। पीपी. 13–14.
- सीके शुक्ला, एस अली, ''बाल श्रम और कानून'', सरूप एंड संसः नई दिल्ली, पीपी –40।
- चौनलेट, एलीशा एमजीएम (1968)। बाल अधिकारों की घोषणा। इंट. बाल कल्याण रेव. यूएन. 22: 144।
- डॉ सचदेवा, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, किताब महल प्रकाशन इलाहाबाद, चौथा संस्करण 2003, पीपी319–320।
- डीएस अल्फ्रेड, ''चिल्ड्रन इन इंडिया'', ऑक्सफैम इंडिया, पीपी –66।
- के.डी. गैंगरेड, 1978, भारत में बाल श्रम। सामाजिक कार्य विभाग, दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय।
- एम.सी.नायडू और के.दशरथ रमैयाः भारत में बाल श्रम–एक सिंहावलोकन जे. समाज. विज्ञान.13 (3) 199–204 (2006)।
- एस, कैलाश, जेड बुपिंदर, ''वैश्वीकरण, विकास और बाल अधिकार।'' नई दिल्लीः शिप्रा प्रकाशन, 2006, पीपी 71–72.
- एस. महापात्रा, एम. दाश, ''बाल श्रम– भारत के लिए सामाजिक–आर्थिक समस्या का एक उत्पाद, निष्कर्ष और निवारक–भुवनेश्वर (भारत की एक राज्य की राजधानी) का एक मामला'', शैक्षिक अनुसंधान, खंड– 2, अंक –6, पीपी–1199–1209, 2011।